श्री अजीत जोगी : : महोदया, शहरीकरण बहुत अबाध गति से बढ़ रहा है। उसके साथ ही शहर में परिवहन की समस्या भी बढ़ रही है। जो शासकीय स्रोतों से समस्या को हल करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा महसूस किया जाता है कि वह पर्याप्त नहीं है और बहुत बार ऐसे सुझाव आए हैं कि निजी स्रोतों का भी इसमें उपयोग किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि अर्बन ट्रांसपोर्ट की जिस नई पालिसी पर वह विचार कर रही है, उसमें क्या प्रायवेटाइजेशन को, निजी स्रोतों को भी शामिल करने का विचार है ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : यह तो स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि क्या उनकी आवश्यकताएं हैं और किस तरह से वे उसको दाखिल करना चाहती हैं। एज ए मैटर आफ पालिसी, जैसेकि मैंने पहले कहा उस वक्त पालिसी हमारी क्या होगी, किस तरह से होगी, उसके बारे में मैं अभी नहीं बता सकती लेकिन जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स के सुझाव आते हैं क्योंकि ज्यादातर तो हर स्टेट गवर्नमेंट की प्रोब्लम्स है उनके सुझाव देखकर कि उनके लिए कौनसी चीज अच्छे ढंग से चल सकेगी उसी के बाद सारी पालिसी फायनलाइज होगी।

*84. [*The questions (Shri Pramod Mahajan and Shri Shankar Sinh Vaghela) were absent. For answer,* vide *cols.* 33 *infra.*] ..

*685. [*The questioners (Dr. Bapu Kaldate and Shri M. S. Gurupadaswamy) were absent. For answer,* vide *cols.* 34 infra.]

Abolition of Lease Hold System in Delhi

*86. SHRI MAHENDRA PRASAD:† DR. RATNAKAR PANDEY:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of a resolution recently passed by the Metropolitan Council of Delhi, demanding abolition of the lease hold system in Delhi; and

(b) if so, what decision Government have taken in regard thereto?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI): (a) Yes, Madam.

(b) The matter is under consideration.

SHRI MAHENDRA PRASAD: The honourable Minister is an efficient Minister. I hope she is aware that the first assurance for consideration was given on 12-3-1980 in Rajya Sabha. How many more seven-year periods will be taken to consider this ordinary thing.

DR. (SHRIMATI NAJMA HEPTULLA): Till he retires.

श्रीमती मोहसिना किदवई : आप ही के जमाने में कोशिश की जाएगी। यह बात सही है कि —

It is a very important thing and the Government is also very keen for conversion of the leasehold into freehold.

SHRI MAHENDRA PRASAD: I hope the honourable Minister is aware that other metropolitan cities like Madras and Bombay have done away with the system of leasehold property. In order to bring about uniformity in all metropolitan cities, will the honourable Minister consider expediting a decision to do away with the leasehold system?

श्रीमती मोहसिना किदवई : जैसा मैंने पहले कहा पूरी अपनी सिसअरिटी के साथ गवर्नमेंट की यह कोशिश है कि खास तौर से जो गरीब तबका है और यह मैं समझती हूं कि डवलपमेंट में भी एक बाधा पड़ती है, इससे, तो यह जो कनवर्सन है यह जल्द-से-जल्द हो जाय। लेकिन इस वक्त जो प्रपोजल्स हैं, उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं कह सकती और न कहना चाहती हूं। मैं इतना ही यकीन दिला सकती हूं कि बहुत जल्द इसके ऊपर कोई-न-कोई निर्णय लिया जाएगा।

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Mahendra Prasad.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय उपसभापति महोदया, ऐसी कौन सी आवश्यकता आ पड़ी जिसके कारण दिल्ली महानगर परिषद ने हाल ही में पट्टा प्रणाली को समाप्त करने की मांग की है और सरकार उस पर विचार कर रही है? इसके साथ ही मैं यह भी चाहूंगा कि विचार किस दिशा में चल रहा है, यह भी माननीय मंत्री महोदया बताने की कृपा करें।

श्रीमती मोहसिना किदवई : महोदया, जैसा मैंने पहले कहा यह सवाल मुख्य रूप से लीज होल्ड को फ्री होल्ड में कन्वर्ट करना है। दिल्ली में तीन तरह की जमीनें हैं। नजूल लीज है, रिहैबिलिटेशन लीज है और डी०डी० ए० की लीज वाली जमीनें हैं। उनके बारे में विचार हो रहा है कि कौन सी लैंड फ्री होल्ड करनी चाहिए और खास तौर से जो रिहैबिलिटेशन लीज है उसके बारे में बहुत ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि बहुत छोटी छोटी जमीनें हैं; छोटे छोटे लोगों के पास हैं, उनको दिक्कतें होती हैं। उनकी परेशानियों को मुद्देनजर रखते हुए सारी प्रपोजल्स जो आ रही हैं उनके बारे में उम्मीद है कि जल्दी कोई फैसला हो जाएगा।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय उपसभापति महोदया, दिल्ली विकास प्राधिकरण की या जो धार्मिक जमीन है उस पर लोग नाजायज तौर से कब्जा कर लेते हैं। उनसे इस जमीन को छुड़ाने के लिए क्या मास्टर प्लान में सुधार करने का सरकार विचार कर रही है?

श्रीमती मोहसिना किदवई : महोदया, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है मास्टर प्लान में सुधार करने का, उसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: A demand for abolition of leasehold has been made by defferent quarters for Chandigarh also. I would like to know from the hon. Minister whether that is also under consideration, active consideration, of the Government and whether in working out the modalities thereof, the public men would also be associated with the exercise.

श्रीमती मोहसिना किदवई : यह सजेशन जो बंसल साहब ने दिया है उसको मैं देखूंगी और जो चीज अच्छी है उसको करने की कोशिश की जाएगी।

डा० (श्रीमती) नजमा हेपतुल्ला : माननीया, मैं मंत्री जी से यह सवाल करना चाहती हूं कि जो लीज होल्ड को फ्री करने का सवाल है क्या इसमें दिल्ली के सारे एम०पीज० ने कहा है कि लीज सिस्टम को ऐबोलिश किया जाए?

श्रीमती मोहसिना किदवई : जितने भी दिल्ली के पब्लिक के नुमाइंदे हैं और खास तौर से हमारे एम०पीज० हैं सबने यही राय जाहिर की है कि लीज होल्ड को फ्री होल्ड में तबदील किया जाए खास तौर से वीकर सेक्शस के हितों को ध्यान में रखते हुए।

.Demolition of Mahavir Enclave in. Delhi

*87. SHRI M. KADHARSHA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to reply to Unstarred Question 2376 given in the Rajya Sabha on 8th May, 1987 and state:

(a) whether it is a fact that Mahavir Enclave in Delhi Cantonment area has been shown as a regularised colony at Sr. No. 390;

(b) if so, what are the reasons that the DDA pressed into action a group of about 200 men who went to Mahavir Enclave on 27th June, 1987 to demolish the authorised construction;

(c) what is the number and details of persons killed in the action and the extent of loss suffered by the residents of the authorised colony named Mahavir Enclave;

(d) whether the persons have since been compensated;

(e) if not, what are the reasons therefor;

(f) by when they are likely to be compensated; and